TITLE CODE:- UPHIN51504

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 222
दि. 13.12.2025,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

राष्ट्रपति ने सभी समुदायों से शांति, समझ और सुलह के प्रयासों में निरंतर सहयोग करने का आग्रह किया

मणिपुर के आदिवासी समुदायों के लिए गरिमा, सुरक्षा और विकास के अवसर सुनिश्चित करना और देश की प्रगति में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना राष्ट्रीय प्राथमिकता है: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु

(जीएनएस)।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (12 दिसंबर, 2025) मणिपुर के सेनापति में एक सार्वजनिक समारोह की शोभा बढ़ाई। उन्होंने इस अवसर पर विकास की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी, साथ ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया।

सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मणिपुर के आदिवासी समुदायों के लिए सम्मान, सुरक्षा और विकास के अवसर तथा देश की प्रगति में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना राष्ट्रीय प्राथमिकता है। भारत सरकार मणिपुर में समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय नेताओं, नागरिक समाज और समुदायों के साथ मिलकर काम कर रही है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार देश के हर कोने तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हाल के वर्षों में, मणिपुर के पहाड़ी जिलों को सड़क और पुल संपर्क, राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों सहित, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पेयजल और बिजली आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में किए गए लक्षित निवेशों से लाभ हुआ है। कौशल प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह और वन धन जैसी आजीविका योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। ये प्रयास आदिवासी समुदायों की अनूठी पहचान और परंपराओं का सम्मान करते हुए उनका समर्थन करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि मणिपुर की ताकत उसकी विविधता, उसकी संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं में निहित है। पहाड़ और घाटी हमेशा से एक-दूसरे के पूरक रहे हैं, मानो एक ही खूबसूरत भूमि के दो पहलू हों। उन्होंने सभी समुदायों से शांति, समझ और सुलह के प्रयासों में सहयोग जारी रखने का आग्रह किया। भारत सरकार मणिपुर के लोगों की आकांक्षाओं को समझती है। उन्होंने मणिपुर के लोगों के कल्याण और प्रगति के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया, जिनमें इस क्षेत्र के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक शांतिपूर्ण और समृद्ध मणिपुर के लिए मिलकर निरंतर काम करना चाहिए।

इससे पहले, राष्ट्रपति ने इम्फाल स्थित नुपी लाल स्मारक परिसर में मणिपुर की वीर महिला योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह स्मारक परिसर मणिपुरी महिलाओं के बलिदान की स्ँ मृति है। यह उनके उन विद्रोहों की याद दिलाता है जिनमें उन्होंने अंग्रेजों और सामंती शक्तियों को अदम्य साहस के साथ चुनौती दी थी।

कुल कृषि उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी 21 प्रतिशत... सीएम योगी ने किया किसान पाठशाला का शुभारंभ

बाराबंकी (जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में किसान पाठशाला और प्रगतिशील किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने किसान पाठशाला में खेती की चुनौतियों और उत्पादन को बढ़ाने पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के पास देश की कुल कृषि भूमि का 11 प्रतिशत हिस्सा है लेकिन यूपी देश के कुल कृषि उत्पादन में 21 फीसदी योगदान देता है। यह बताता है कि प्रदेश का किसान मेहनती भी है और नवाचार की क्षमताओं से भी भरपूर है। सरकार प्रदेश के 28 जिलों में 4000 करोड़ की लागत से खेती में सुधार और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है।

सीएम योगी शुक्रवार को हरख ब्लॉक के दौलतपुर गांव में पद्मश्री और प्रगतिशील किसान रामसरन वर्मा के फार्म पर आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने दौलतपुर में किसान पाठशाला और प्रगतिशील किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से तमाम योजनाएं चलाई हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, पीएम किसान सम्मान निधि, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी ने बड़े स्तर पर किसानों को राहत दी है।

सीएम योगी ने कहा कि परंपरागत खेती के साथ-साथ यदि किसान उच्च मूल्य वाली फसलों, सब्जियों, फल उत्पादन और प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़ें तो उनकी आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। उन्होंने पद्मश्री रामसरन वर्मा का उदाहरण देते हुए कहा कि वैज्ञानिक तकनीकों और नवाचार को अपनाने से सीमित भूमि पर भी शानदार उत्पादन संभव है। सरकार किसानों को इसी दिशा में प्रोत्साहित कर रही है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल से 'कोलसेतु' विंडो को मंजूरी, पीएम मोदी बोले- इज ऑफ डूइंग बिजनेस में मिलेगी मदद

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने शुक्रवार को कोयला लिंकेज की नीलामी नीति में सुधार करते हुए निर्बाध, कुशल और पारदर्शी उपयोग (कोलसेतु) के लिए नई विंडो को मंजूरी दे दी है। इस नई विंडो के माध्यम से किसी भी औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए कोयले का आवंटन किया जा सकेगा। इसे एनआरएस लिंकेज नीति में शामिल किया गया है। यह कदम कोयला क्षेत्र में सरकार के चल रहे सुधारों को और गति देगा।

कोयले के आसान, कुशल और पारदर्शी इस्तेमाल के लिए एक नया रास्ता

इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'कैबिनेट ने 'कोलसेतु' पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिससे कोयले के आसान, कुशल और पारदर्शी इस्तेमाल के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। इससे इज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद मिलेगी, देश में कोयले की उपलब्धता बढ़ेगी और आयातित कोयले पर निर्भरता कम होगी। यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और विकास को तेज करेगा।'

लिंकेज नीलामी नीति में 'कोलसेतु' नामक अलग विंडो

नई नीति 2016 की एनआरएस (नॉन-रेगुलेटेड सेक्टर) लिंकेज नीलामी नीति में 'कोलसेतु' नामक अलग विंडो जोड़ती है, जिसके तहत नीलामी के माध्यम से दीर्घकालिक कोयला लिंकेज किसी भी घरेलू औद्योगिक उपभोक्ता या निर्यात उद्देश्य के लिए आवंटित किया जा सकेगा।

एआई का विवेकपूर्ण इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवा के लिए वरदान साबित हो सकता है: डॉ. जितेंद्र सिंह

भारत में जैव प्रौद्योगिकी के भविष्य के लिए सरकार और उद्योग जगत की साझेदारी महत्वपूर्ण है, डॉ. जितेंद्र सिंह ने जीन थेरेपी और जैव प्रौद्योगिकी में बढ़ते सार्वजनिक-निजी सहयोग पर प्रकाश डाला "भारत का फार्मा क्षेत्र निवारक स्वास्थ्य देखभाल के आयातक से वैश्विक निर्यातक में परिवर्तित हो रहा है" विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज इस बात पर जोर दिया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का विवेकपूर्ण इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवा और फार्मा क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो सकता है।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी कमेटी का 20वां सत्र नई दिल्ली में सफलतापूर्वक खत्म हुआ

(जीएनएस)।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की सुरक्षा के लिए वठएरउड की अंतर सरकारी कमेटी का 20वां सत्र आज नई दिल्ली के लाल किले में सफलतापूर्वक खत्म हुआ। संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री विवेक अग्रवाल ने अपने भाषण में इस प्रतिष्ठित वैश्विक बैठक की मेजबानी करने पर भारत की ओर से गहरी खुशी जाहिर की और जीवित विरासत की सुरक्षा, प्रचार और जश्न मनाने के लिए देश के लगातार प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया।

श्री विवेक अग्रवाल ने कहा कि पिछले दिनों की बातचीत और विचार-विमर्श से प्रतिनिधियों को न केवल कन्वेंशन के काम करने के तरीकों से जुड़ने का मौका मिला, बल्कि उन्हें भारत की सांस्कृतिक समृद्धि, सबको साथ लेकर चलने और अलग-अलग तरह की परंपराओं का भी अनुभव करने का मौका मिला। उन्होंने संस्कृति को एक सामूहिक विरासत के रूप में देखने के भारत के लंबे समय से चले आ रहे सभ्यतागत नजरिए पर जोर दिया, जो इस सिद्धांत से चलता है: 'संस्कृतिः रक्षणं, लोकस्य रक्षणम्' संस्कृति की रक्षा करके, हम मानवता की रक्षा करते हैं।

इस साल के सत्र की एक खास बात थी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की वठएरउड की प्रतिनिधि सूची में दीपावली का नाम शामिल होना। श्री अग्रवाल ने कहा कि भारत और उसके बाहर बड़े पैमाने पर मनाई जाने वाली दीपावली रोशनी, उम्मीद और नई जान डालने का प्रतीक है, और इसका नाम शामिल होना भारत की जीवंत परंपराओं की वैश्विक पहचान को और मजबूत करता है। उन्होंने उन सभी सदस्य देशों को बधाई दी जिनके सिद्धांतों को इस सत्र के दौरान नाम शामिल करने की मंजूरी मिली। सेशन के दौरान हुई चचाओं पर बात करते हुए, श्री अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समुदायों को बनाए रखने, सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने और परंपराओं की निरंतरता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्वीकरण, संघर्ष और जलवायु से जुड़े दबाव दुनिया भर के सांस्कृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर असर डाल रहे हैं।

श्री अग्रवाल ने कहा कि कई देशों ने बहुराष्ट्रीय अमूर्त विरासत नामांकन में ठोस दिलचस्पी दिखाई है, यह मानते हुए कि कई परंपराएँ स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय सीमाओं को पार करती हैं। भारत ने इस मिलकर काम करने की भावना का स्वागत किया और आने वाले सालों में मिलकर अंतरराष्ट्रीय नामांकन का विकास करने के लिए अपनी तैयारी की पुष्टि की। श्री अग्रवाल ने वठएरउड के डायरेक्टर-जनरल डॉ. खालिद अल-एनानी, वठएरउड में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव श्री विशाल वी. शर्मा, सेक्रेटरी सुश्री फुमिको ओहिनाता, सदस्य देशों, मान्यता प्राप्त ठऋडर, सांस्कृतिक व्यवसायी, और विशेषज्ञों का सत्र को असरदार बनाने में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए भारत की तरफ से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाले संस्थान जैसे संगीत नाटक अकादमी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, क्ऋठउअ, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की कोशिशों की भी तारीफ की, जिन्होंने इस कार्यक्रम की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में अहम भूमिका निभाई।

अपना भाषण खत्म करते हुए, सचिव ने सभी सदस्य देशों से वैश्विक सांस्कृतिक एकता की भावना को बढ़ावा देते रहने की अपील की, और अथर्ववेद का ज़िक्र किया: 'समानि वः वृणुते हृदयानि' हमारे दिल एकता का रास्ता चुनें। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए सत्र के दौरान रखे गए लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और सहयोग को मजबूत करने के लिए तैयार है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की तीसरी आम सभा बैठक की अध्यक्षता की।

- श्री भूपेन्द्र यादव ने भारत के समुद्री उत्पत्ति स्थल के संरक्षण और सतत प्रबंधन पर संस्थान के वैज्ञानिक योगदानों की समीक्षा की
- वैज्ञानिक काडर की क्षमता वृद्धि को मजबूत करें, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और सामुदायिक भागीदारी के गहन एकीकरण के साथ विज्ञान-आधारित नीतिगत सहभागिता को बढ़ावा दें: सामान्य निकाय

(जीएनएस)।

केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम) की तीसरी आम सभा (जीबी) बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने केंद्र के अध्यक्ष के रूप में बैठक का नेतृत्व किया। विचार-विमर्श के इस सत्र में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और आम सभा के सदस्य भी सम्मिलित हुए। इस बैठक में तटीय और समुद्री अनुसंधान तथा प्रबंधन के क्षेत्र के विशेषज्ञों और जाने-माने वैज्ञानिकों ने भी भाग लिया।

श्री यादव ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के आकलन, जलवायु अनुकूलन और समुद्री प्राकृतिक आवासों के पुनर्स्थापन के क्षेत्रों में एनसीएससीएम के वैज्ञानिक योगदानों की समीक्षा की। बैठक में एनसीएससीएम ने संरक्षण से लेकर आजीविका, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, द्वीपीय स्थिति, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी, तटीय प्रक्रियाओं, समुद्र तटीय स्थानिक योजनाओं और एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन जैसे प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों पर प्रस्तुति दी।

आम सभा (जीबी) ने संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने सहित कार्यक्रमों में वैज्ञानिक प्रयासों को सुदृढ़ करने और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों और पारंपरिक ज्ञानवान लोगों के साथ सहयोगपूर्ण सहभागिता का विस्तार करने के निर्देश दिए। एनसीएससीएम को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया कि उसके अनुसंधान और क्षमता-निर्माण पहलों में विज्ञानझनीतिझसमुदाय के एकीकरण को और गहरा किया जाए। जीबी ने यह भी निर्देश दिया कि एनसीएससीएम के विजन दस्तावेज को विकसित भारत 2047 की थीम के अनुरूप अंतिम रूप दिया जाए।

जीबी ने तटवर्ती क्षेत्रों और समुद्री क्षेत्रों में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक काडर की क्षमता को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए, जिसमें महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पदों पर नियुक्तियाँ और नई प्रतिभाओं को आगे लाना शामिल है। भर्ती नियमों से संबंधित एचआर नीति पर भी चर्चा की गई और इसे शीघ्र ही अंतिम रूप देने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में वैज्ञानिक अधिगम और क्षेत्र-आधारित अनुसंधान में रुचि बढ़ाने के लिए इको-क्लबों, स्थानीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों की सहभागिता बढ़ाने के महत्व को भी रेखांकित किया गया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का ई-ग्राम विश्वग्राम सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी की बैठक में संवेदनशील निर्णय

- वीसीई को राज्य सरकार के विभागों द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यों के लिए प्रति यूनिट न्यूनतम 20 रुपए का भुगतान किया जाएगा

(जीएनएस)।

गांधीनगर, 12 दिसंबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में कमीशन के आधार पर ग्राम कंप्यूटर उद्यमी (वीसीई) के तौर पर काम करने वाले युवाओं की अधिकतम आय सुनिश्चित करने वाला संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने इस संदर्भ में यह निर्णय किया है कि वीसीई को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा सौंपे गए कार्यों के लिए प्रति यूनिट न्यूनतम 20 रुपए का भुगतान किया जाएगा।

राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के जरिए शहरी क्षेत्र में उपलब्ध ई-सेवाओं जैसी ही सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में मुहैया कराने के उद्देश्य से 'ई-ग्राम विश्वग्राम योजना' लागू की है।

उल्लेखनीय है कि ग्राम कंप्यूटर उद्यमी (वीसीई), ग्राम स्तर पर लोगों को 7/12, 8-अ और अधिकार पत्र की प्रतिलिपि, किसान रजिस्ट्रेशन, विभिन्न खेत उपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड में संशोधन करने के लिए फॉर्म भरने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से वीसीई को विभिन्न योजनाओं की डेटा एंट्री से संबंधित कार्य भी सौंपा जाता है। इसके लिए संबंधित विभाग प्रत्येक कार्य के लिए वीसीई को प्रति यूनिट कमीशन के रूप में देय राशि निर्धारित करता है।

इसके कारण, अलग-अलग कामकाज और अलग-अलग विभागों द्वारा निर्धारित की जाने वाली मेहनताने की राशि अलग-अलग आधार पर तय होने से मेहनताने में समानता नहीं रह पाती।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के ध्यान में जब यह विषय आया, तब उन्होंने हाल ही में ई-ग्राम विश्वग्राम सोसाइटी की गांधीनगर में आयोजित 12वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए वीसीई के मेहनताने में समानता के लिए तत्काल निर्देश दिए थे।

मुख्यमंत्री के इन दिशा-निर्देशों के चलते पंचायत विभाग ने परिपत्र जारी कर राज्य सरकार के विभागों को सूचित किया है कि अब किसी भी कार्य के लिए वीसीई को प्रति यूनिट न्यूनतम 20 रुपए का मेहनताना देना होगा।

इतना ही नहीं, संबंधित विभागों को वीसीई को कामकाज सौंपने से पहले पंचायत विभाग तथा ई-ग्राम विश्वग्राम सोसाइटी को जानकारी भी देनी होगी।

सम्पादकीय

भारतीय विदेश मंत्री के बयान पर पाकिस्तान ने किया विरोध

पाकिस्तान का जवाब पाकिस्तान ने अपनी सेना और इसके प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी पर बयान जारी किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर जयशंकर का बयान भड़काऊ, बेबुनियाद और गैर-जिम्मेदाराना है। बता दें कि जयशंकर ने हिन्दुस्तान टाइम्स समिट के दौरान आसिम मुनीर के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा था कि पाकिस्तान में आज जो हो रहा है वो इसके 80 साल पुराने इतिहास का प्रतिबिंब है। जयशंकर ने ये भी कहा था कि पाकिस्तान में किसी न किसी तरीके से सेना ही शासन करती है। कभी सेना खुलकर काम करती है, कभी पर्दे के पीछे से। बीबीसी के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार देश है और उसकी सभी संस्थाएं जिनमें सशस्त्र बल भी शामिल हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मजबूत स्तंभ हैं। यह संस्थाएं देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रवक्ता ने कहा मई 2025 के संघर्ष ने साफतौर पर पाकिस्तानी सेना की पेशेवर क्षमता और मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके संकल्प को साबित कर दिया है। कोई भी दुष्प्रचार अभियान इस सच्चाई को नकार नहीं सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की संस्थाओं और नेतृत्व को बदनाम करने की भारतीय नेतृत्व की कोशिश एक सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा है। इसका मकसद क्षेत्र में भारत की अस्थिर करने वाली बयानबाजी शांति और स्थिरता के प्रति भारत की गंभीरता की कमी दर्शाती है। बता दें कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि जिस तरह अच्छे आतंकवादी और बुरे आतंकवादी जैसी बातें की जाती हैं। उसी तरह अपने सैन्य नेता और उतने अच्छे सैन्य नेता नहीं होने की बात भी की जाती है। हिन्दुस्तान टाइम्स समिट में जयशंकर से यह भी पूछा गया था कि पाकिस्तान में नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हाथ में जिस तरह सत्ता का बहुत ज्यादा केंद्रीकरण देखा जा रहा है। उस पर आप क्या-क्या आंकलन है? आसिम मुनीर का इतनी गहराई से सत्ता में पंसे होने का भारत को फायदा है या नुकसान? जयशंकर ने कहा कि भारत के लिए पाकिस्तानी सेना हमेशा एक वास्तविक की तरह रही है। अगर हम बात करें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तो केवल हम ही नहीं उनके हाथ में भी इतनी शक्ति आने से संयुक्त राष्ट्र भी चिंतित है। पाकिस्तान में हाल में हुए संविधान संशोधन को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी के उच्चायुक्त वोल्कर टर्व ने चेतावनी दी है कि 27वें संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकते हैं। टर्व ने एक बयान में कहा कि यह बदलाव उन जरूरी कानूनी नियमों को भी कमजोर कर सकता है, जिनसे देश में कानून-व्यवस्था बनी रहती है। बता दें कि पाकिस्तान में हालिया संवैधानिक बदलावों के बाद अब सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में स्थापित हो गए हैं। उन्हें गत दिनों चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस (सीडीएफ) बनाया गया है और इसी के साथ सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और मिसाइल नियंत्रण भी उनके हाथ आ गया है। नया तंत्र उन्हें वास्तविक परमाणु बटन का नियंत्रक बना रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार परमाणु हथियारों के नियंत्रण को इतनी स्पष्टता से सेना को सौंपा गया है कि इससे न केवल सैन्य प्रतिष्ठान की ताकत चरम पर पहुंच गई है, बल्कि जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की राजनीति, सामरिक नीतियों और क्षेत्रीय शक्ति समीकरणों में सबसे निर्णायक और प्रभावशाली व्यक्तित्व बना दिया है।

बच्चों को केजी से पीजी तक की शिक्षा आसानी से उपलब्ध कराने का प्रधानमंत्री का लक्ष्य पूरा हो रहा है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विभिन्न शिक्षा योजनाओं के तहत 13 लाख से अधिक छात्रों को 370 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति सहायता वितरित की
- उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, शिक्षा मंत्री श्री प्रद्युमन वाजा और शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रीवाबा जाडेजा की प्रेरक उपस्थिति
- नमो लक्ष्मी योजना, नमो सरस्वती विज्ञान साधना, मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप और मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु मेरिट स्कॉलरशिप योजना के लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए सहायता वितरित
- राज्य सरकार ने अनेक शैक्षणिक योजनाएं कार्यरत कीं, ताकि छात्रों पर आर्थिक बोझ न पड़े : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी
- शिक्षा में किया गया निवेश केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि विकसित गुजरात के निर्माण की मजबूत नींव है : शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा

गांधीनगर, 12 दिसंबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, शिक्षा मंत्री श्री प्रद्युमन वाजा और शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रीवाबा जाडेजा की उपस्थिति में नमो लक्ष्मी योजना, नमो सरस्वती विज्ञान साधना, मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप और मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु मेरिट स्कॉलरशिप योजना के 13 लाख से अधिक लाभार्थी छात्रों को 370 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए हस्तांतरित की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पिछले ढाई दशक में राज्य में शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री का बच्चों को केजी से पीजी तक की शिक्षा आसानी से उपलब्ध कराने का लक्ष्य साकार हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद छात्र माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा भी सफलतापूर्वक पूर्ण करें तथा कन्या शिक्षा को अधिक प्रोत्साहन मिले, इसकी चिंता करते हुए नमो लक्ष्मी योजना और नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजनाएं शुरू की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'बेटी बचाओ' अभियान के जरिए देश में बेटियों की शिक्षा को काफी बड़ी गति दी है। श्री पटेल ने कहा कि जब उन्होंने 2001 में गुजरात का सेवादायित्व संभाला, तब अनेक समस्याएं थीं। श्री नरेन्द्र मोदी ने ऐसे समय में देश में एक उदाहरण पेश किया कि, किस प्रकार एक राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं गांव-गांव जाकर बेटियों की शिक्षा का सेवा-यज्ञ शुरू करता है।

इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री उन्हें मिलने वाले उपहारों की नीलामी करके उससे प्राप्त होने वाली राशि को कन्या केळवणी (शिक्षा) के लिए देने की एक नई परंपरा शुरू की। इन सभी के परिणामस्वरूप लोगों में भी बेटियों को स्कूल भेजने की जागरूकता बढ़ी और शाला प्रवेशोत्सव-कन्या केळवणी महोत्सव की सफलता के चलते बेटियों के ड्रॉपआउट की दर 37 फीसदी से घटकर 2 फीसदी से भी नीचे आ गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब गांवों में विज्ञान संकाय के स्कूलों की संख्या बहुत ही कम थी जबकि आज विज्ञान संकाय के स्कूलों की संख्या 2834 हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि 2001 में केवल 775 कॉलेज थे, आज गुजरात में 3200 से अधिक कॉलेज छात्रों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कक्षा 12 में

विज्ञान संकाय के बाद इंजीनियरिंग में पढ़ाई के लिए जाना हो, तो केवल 139 कॉलेज थे, आज इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 288 पर पहुंच गई है। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात में श्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवादायित्व संभाला तब 1175 मेडिकल सीटें थीं, जो आज बढ़कर 7000 से अधिक हो गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल में पढ़ाई करने वाली बेटियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री कन्या केळवणी निधि योजना से अब तक राज्य की 24 हजार से अधिक बेटियों को सहायता प्रदान की गई है।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात और देश का भविष्य जिनके हाथों में हैं, ऐसे आज के छात्रों के लिए गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई फ्लैगशिप योजनाओं में से चार योजनाओं के अंतर्गत आज 13 लाख से अधिक छात्रों के बैंक खातों में सीधे 370 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति सहायता डीबीटी के जरिए भेजी गई है। अब तक, राज्य सरकार ने इन चारों योजनाओं के अंतर्गत कुल 13.50 लाख से अधिक छात्रों को 1332 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की है।

श्री हर्ष संघवी ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को उनके दूसरे कार्यकाल के तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने के अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के नागरिकों के हित में अनेक निर्णय लिए हैं और अपने स्वभाव के अनुसार सौम्यता के साथ पूरे मंत्रिमंडल की टीम को भी इसी प्रकार जनहित के निर्णय लेने के लिए लगातार प्रेरणा, छूट और हिम्मत दी है। शिक्षा विभाग की जिन चार योजनाओं के तहत आज छात्रवृत्ति सहायता दी गई है, उनमें से एक फ्लैगशिप योजना भी उनके ही निर्णय का हिस्सा है। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस प्रकार के प्रत्येक कार्यक्रम में उपस्थित रहकर मुख्यमंत्री ने यह साबित कर दिखाया है कि शिक्षा विभाग और हमारे भविष्य इन छात्रों के लिए उनका कितना समर्पण और योगदान है।

श्री संघवी ने नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना के बारे में कहा कि गुजरात में जिस तरह से बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, ऐसे में यह जरूरी है कि हमारे छात्र भी उसमें अपना योगदान दे सकें। यदि कोई माता-पिता अपने बच्चे को विज्ञान संकाय में पढ़ाना चाहते हों, तो उन पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े, इन नेक विचारों के साथ राज्य सरकार ने यह महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसका राज्य के अनेक छात्र लाभ उठा रहे हैं।

शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा ने छात्रवृत्ति वितरण के अवसर पर कहा कि गुजरात सरकार विकसित गुजरात से विकसित भारत के निर्माण में शिक्षित और सक्षम समाज का निर्माण करने के लिए अडिग है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग देश का भविष्य यानी आज के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए योग्य दिशा देने को संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षा में किया गया यह निवेश केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि आने वाले समय के विकसित गुजरात के निर्माण की मजबूत नींव है। ये महत्वपूर्ण कदम गुजरात के छात्रों के जीवन को एक नई दिशा, नए अवसर और नए सपने देंगे।

गुजरात सरकार द्वारा शिक्षा को प्राथमिकता देने वाली चार महत्वपूर्ण योजनाओं से आ रहे बदलावों की चर्चा करते हुए श्री वाजा ने कहा कि इन योजनाओं से लाखों छात्रों के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण हो रहा है। नमो लक्ष्मी योजना बेटियों के सशक्तिकरण का शक्तिशाली माध्यम बनी है। इस योजना के तहत अब तक 10.49 लाख बेटियों को डीबीटी के जरिए 1033 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। इसके चलते बेटियों की उपस्थिति में 73 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा कक्षा 12 में प्रवेश लेने वाली बेटियों की संख्या में 13.59 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।

शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना के माध्यम से विज्ञान संकाय में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए 1.5 लाख छात्रों को 151.84 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है, जिससे विज्ञान संकाय के नामांकन में 6.34 फीसदी की वृद्धि हुई है। मेरिट और गुणवत्ता पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने वाली अन्य दो योजनाएं- मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत 50,000 छात्रों को 86.14 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु मेरिट स्कॉलरशिप योजना के तहत 60,000 छात्रों को 61.27 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। उन्होंने कहा कि ये चारों योजनाएं गुजरात के लाखों छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए ज्ञानसेतु का निर्माण कर रही हैं।

शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रीवाबा जाडेजा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को उद्धृत करते हुए कहा कि शिक्षा समाज में सकारात्मक बदलाव और प्रत्येक बालक को सशक्त बनाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस विचार को साकार करने वाले आज के कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा 13 लाख से अधिक छात्रों को डीबीटी के जरिए 370 करोड़ रुपए की सहायता पहुंचाने का यह एक ऐतिहासिक अवसर है।

श्रीमती जाडेजा ने आगे कहा कि हमारे देश का प्रत्येक बालक उज्ज्वल भारत का स्वप्न है, इसलिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार नमो लक्ष्मी, नमो सरस्वती सहित अनेक योजनाओं के जरिए बच्चों के सर्वांगीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य को केंद्र में रखकर लगातार कार्यरत है। इसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही आधारभूत सुविधाओं में लगातार वृद्धि करना, कन्या शिक्षा को बढ़ावा देना, ड्रॉपआउट अनुपात को कम करना और बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ राज्य के छात्रों को श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान कर सुंदर भविष्य बनाने का प्रयास करना है।

कार्यक्रम में गांधीनगर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिल्पाबेन पटेल, महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, गांधीनगर शहर संगठन प्रमुख डॉ. आशीष दवे, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री मुकेश कुमार, निदेशक, स्कूल कार्यालय श्री प्रजेश राणा, शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे।

इशिता राज और सिद्धांत कपूर की 'ह्यूमन कोकेन' का ट्रेलर रिलीज

'ह्यूमन कोकेन' का ट्रेलर विभिन्न डिजिटल और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जारी कर दिया गया है, और इसे लेकर शुरूआती प्रतिक्रियाएँ भी आने लगी हैं। 2 मिनट और 8 सेकंड का यह ट्रेलर दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है, जिसमें कई ऐसे दृश्य हैं जो गहन विचार-विमर्श के लिए मजबूर करते हैं। यह फि ल्म ड्रग रैकेट, अपराध और अस्तित्व की अनदेखी दुनिया की एक कच्ची और अशांत झलक देने का वादा करती है, जिसमें चौंकाने वाले और तीव्र पल भरे हुए हैं।

ट्रेलर में, पुष्कर जोग पूरी तरह से बदले हुए अंदाज में नजर आते हैं, एक ऐसे बंदी के रूप में जो एक खतरनाक और अटूट जाल में फँस चुका है। वहीं, इश्ता राज, जो अपने रोमांटिक किरदारों के लिए जानी जाती हैं, पहली बार एक डार्क, ग्रिटी और ग्रंज अवतार में दिखाई देती हैं। यह उनके एक्टिंग टैलेंट की बहुमुखी प्रतिभा को उजागर करता है। पुष्कर के साथ बंधक बनी इशिता अपने अभिनय में एक जमीनी और भावनात्मक गहराई लाती हैं, जिससे हर फ्रेम में तनाव और बढ़ जाता है।

सिद्धांत कपूर अपने अनोखे लुक के साथ एक खास प्रभाव छोड़ते हैं। ट्रेलर में वे काले मिनी ड्रेस में दिखते हैं, जो उनके रहस्यमयी और तेज-

तर्रार किरदार को और भी धार देता है। वरिष्ठ अभिनेता जाकिर हुसैन एक डरावने और शक्तिशाली किरदार में हैं, जो अपनी भयावह उपस्थिति से दर्शकों पर एक गहरी छाप छोड़ते हैं। यह सभी कलाकार फिल्म की गंभीरता को बढ़ाने में सहायक हैं।

'ह्यूमन कोकेन' एक नई, बेहद महंगी कोकीन वैरिएंट के उदय की कहानी बताती है, जिसे एक अत्यंत क्रूर और विचलित करने वाली प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। जैसे-जैसे यह डरावनी हकीकत सामने आती है, पुष्कर जोग और इशिता राज खुद को इसके अंधेरे और खतरनाक चक्रव्यूह में फँसा हुआ पाते हैं। यह फि ल्म वास्तविक घटनाओं से प्रेरित एक दमदार कहानी पेश करती है, जो अंडरवर्ल्ड के उस अनदेखे हिस्से पर से पर्दा उठाती है।

फि ल्म के बारे में बात करते हुए, अभिनेता पुष्कर जोग ने बताया, "'ह्यूमन कोकेन' ने मुझे एक कलाकार और एक इंसान के तौर पर चुनौती दी। मेरा किरदार अपनी परिस्थितियों में फँसा हुआ है, जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। वह बेबसी, वह डर, वह गुस्सा-कैमरा बंद होने के बाद भी मेरे साथ बना रहा। यह मेरे करियर की सबसे तीव्र परियोजनाओं में से एक है।"

लेखक और निर्देशक सरिम मोमिन ने इस प्रोजेक्ट पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, "'ह्यूमन कोकेन' हमारे आसपास मौजूद एक डरावनी हकीकत का प्रतिबिंब है। इसे सहज या आसान देखने के लिए नहीं बनाया गया है। इसका उद्देश्य है परेशान करना, सोचने पर मजबूर करना और बातचीत शुरू करना। इस फि ल्म का हर किरदार समाज के उस पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे हम अक्सर छिपा देते हैं।"

इशिता राज, सिद्धांत कपूर, जाकिर हुसैन और ब्रिटिश कलाकारों की एक सशक्त टीम से सजी यह फि ल्म एक गहरा अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य रखती है। सरिम मोमिन द्वारा निर्देशित और लिखित इस फि ल्म को स्कारलेट स्लेट स्टूडियोज, वाइनलाइट लिमिटेड और टेक्स्टस्टेप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने गूजबम्प्स एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर निर्मित किया है।

डीएम का आदेश, शिक्षकों में हड़कंप! स्कूल के आठ किमी के दायरे में रहेंगे टीचर, जानिए क्यों

(जीएनएस)।

उत्तराखंड के टिहरी में डीएम के एक आदेश की प्रदेशभर में चर्चा हो रही है। टिहरी की जिलाधिकारी निकिता खंडेलवाल ने शिक्षकों के आठ किमी के दायरे में रहने संबंधी आदेश को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए थे। जिसके बाद एक बार फिर ये आदेश चचाओं में आ गया है।

आदेश के मुताबिक, संबंधित विद्यालय के आठ किलोमीटर के दायरे में ही शिक्षक निवास करेंगे। शिक्षक संगठन इस आदेश को लेकर पहले से ही आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। हालांकि शिक्षा विभाग का दावा है कि इस तरह का नियम पहले से ही सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग में है।

टिहरी के कीर्तिनगर में तहसील

दिवस पर जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाया था और वहां फरियादी अपनी शिकायतों के समाधान के लिए पहुंच रहे थे। उसी बीच एक फरियादी ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता पर सवाल उठाए और टीचरों की जवाबदेही तय करने की मांग कर डाली। उन्होंने डीएम को बताया कि, 'सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को लेकर शिक्षकों का ध्यान बेहद कम है।

ज्यादातक टीचर दूरदराज इलाकों से वाहनों के जरिए स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल में मात्र औपचारिकता पूरी करते है। फिर शाम को वापस लौट जाते हैं। उनकी मांग थी कि शिक्षक स्कूल के आसपास ही रहें ताकि वो विद्यालय और छात्रों पर ध्यान दे पाएं। जिलाधिकारी टिहरी निकिता खंडेलवाल ने संबंधित अधिकारियों को इस बाबत औपचारिक आदेश जारी करने को कहा था।

आदेश के मुताबिक, संबंधित विद्यालय के आठ किलोमीटर के दायरे में ही शिक्षक निवास करेंगे। टिहरी में इसी स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने शिक्षकों के विद्यालय से 8 किलोमीटर के दायरे में ही रहने के निर्देश दे दिए, जिस पर नईब बहस शुरू हो गई है। जिलाधिकारी का ये आदेश काफी चचाओं में आ गया है। शिक्षक संगठन पहले ही इस तरह के आदेश को अव्यवहारिक बता चुके हैं। जिसके बाद एक बार फिर शिक्षक संगठन और विभाग में खींचतान होनी तय है।

सेमीकंडक्टर के डिजाइन, निर्माण, संयोजन, परीक्षण और पैकेजिंग के लिए सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम एक संपूर्ण व्यवस्था विकसित कर रहा है

- उत्पादन और डिजाइन से जुड़े प्रोत्साहनों के अलावा, सरकार सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रतिभाओं के विकास पर भी काम कर रही है

(जीएनएस)।

सेमीकंडक्टर विकास रणनीति, माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन से प्रेरित है।

अर्थव्यवस्था के लिए सेमीकंडक्टर उद्योग की मूलभूत प्रकृति को देखते हुए, सरकार ने डिजाइन, निर्माण, संयोजन, परीक्षण और पैकेजिंग सहित एक संपूर्ण व्यवस्था तैयार करने के लिए 'सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम' शुरू किया।

सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए पीएलआई योजनाओं के तहत निम्नलिखित निवेश प्राप्त हुए हैं:

सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत, 1.6 लाख करोड़ रुपये के निवेश से दस (10) इकाइयों को मंजूरी दी गई है, जिनमें सिलिकॉन फैब, सिलिकॉन कार्बाइड फैब, उन्नत पैकेजिंग, मेमोरी पैकेजिंग आदि शामिल हैं।

ये इकाइयां उपभोक्ता उपकरण, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, एयरोस्पेस और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्रों की चिप की जरुरतों को पूरा करेंगी।

मंजूर प्रस्तावों में से कुछ सेमीकंडक्टर चिप्स की असेंबली, परीक्षण और पैकेजिंग के लिए स्वदेशी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं।

सरकार ने मोबाइल फोन और कुछ विशिष्ट घटकों के बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) शुरू की है। इस योजना के तहत अक्टूबर 2025 तक 14,065 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हो चुका है।

आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को लक्षित करते हुए, सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (यूएसएफएफ) उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई

शुरू की।

आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई के तहत अक्टूबर 2025 तक 846 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है।

इन नीतिगत प्रयासों के नतीजतन, पिछले 11 सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण करीब 6 गुना बढ़ गया है। यह 2014-15 में 1.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 11.32 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात आठ गुना बढ़कर 2014-15 में 38 हजार करोड़ रुपये से 2024-25 में 3.26 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स अब निर्यात की तीसरी सबसे बड़ी श्रेणी है।

डिजाइन इकोसिस्टम को बढ़ावा देना

चिप डिजाइन में भारत की क्षमता का लाभ उठाने के लिए, सरकार ने डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना की शुरूआत की।

उपग्रह संचार, ड्रोन, निगरानी कैमरा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) उपकरण, एलईडी ड्राइवर, एआई उपकरण, दूरसंचार उपकरण, स्मार्ट मीटर आदि उत्पादों के लिए चिप्स और एसओसी डिजाइन करने के लिए 23 कंपनियों (24 डिजाइनों) को सहायता प्रदान की गई है।

इसके अलावा, ढ़ांचागत सहायता के रूप में, 94 स्टार्टअप्स को निशुल्क डिजाइन टूल (ईडीए) की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे 47 लाख घंटे का डिजाइन टूल उपयोग संभव हुआ है।

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रतिभाओं का विकास

सरकार ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रतिभाओं का विकास करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है:

चिप्स टू स्टार्टअप (सी2एस) कार्यक्रम: भारत के युवा इंजीनियरों को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार 397 विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप्स को नवीनतम डिजाइन टूल (ईडीए) उपलब्ध करा रही है।

इन टूल का इस्तेमाल करके, 46 से अधिक विश्वविद्यालयों के चिप डिजाइनरों ने मोहाली स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल) में 56 चिप्स डिजाइन और निर्मित किए हैं।

चिप डिजाइन में अब तक 67,000 से अधिक छात्रों और शोधकताओं को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने निम्नलिखित पाठ्यक्रम शुरू किए हैं:

इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (वीएलएसआई डिजाइन) में बी.टेक,

इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) निर्माण में डिप्लोमा, और

इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (वीएलएसआई डिजाइन और प्रौद्योगिकी) में माइनर डिग्री

1 लाख इंजीनियरों को राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण देने के मकसद से एनआईईएलआईटी कालीकट में एक कुशल मानव संसाधन उन्नत अनुसंधान और प्रशिक्षण (स्मार्ट) प्रयोगशाला स्थापित की गई है। अब तक 62 हजार से अधिक इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

आईएसएम ने नैनोफैब्रिकेशन और प्रोसेस-इंजीनियरिंग कौशल में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए लैम रिसर्च के साथ साझेदारी की है। इससे एटीएमपी और उन्नत पैकेजिंग के लिए कुशल कार्यबल में और वृद्धि होगी। इस कार्यक्रम का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 60,000 प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना है।

फ्यूचरस्किल्स प्राइम कार्यक्रम भारत को अत्याधुनिक डिजिटल प्रतिभाओं का देश बनाने के मकसद से एमईआईटीवाई और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) की एक संयुक्त पहल है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

सेमीकंडक्टर जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में कौशल विकास, पुनः कौशल विकास और उन्नत कौशल विकास।

रोजगार की असल जरुरतों के मुताबिक उद्योग के परामर्श से पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

रेल सुरक्षा रिकॉर्ड सुधार में वृद्धि : वार्षिक दुर्घटनाएं 2004-14 के औसत 171 से घटकर 2025-26 में अब तक 11 रह गई हैं

- सुरक्षा बजट लगभग तीन गुना बढ़कर 2013-14 के 39,463 करोड़ रूपए से चालू वित्त वर्ष में 1,16,470 करोड़ रूपए हो गया है
- अश्विनी वैष्णव ने कहा- कोहरे से बचाव के उपकरणों की संख्या 288 गुना बढ़ी है — 2014 के 90 से बढ़कर 2025 में 25,939 हो गई है
- पिछले चार महीनों में 21-21 स्टेशनों पर केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और ट्रैक-सर्किट का काम पूरा हो गया है

(जीएनएस)। भारतीय रेल में यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। किसी भी असामान्य घटना की रेलवे प्रशासन द्वारा गहन जांच की जाती है। तकनीकी कारणों के अलावा किसी अन्य कारण की आशंका होने पर राज्य पुलिस की सहायता ली जाती है।

कुछ मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से भी मार्गदर्शन लिया जाता है। हालांकि, जांच का प्राथमिक माध्यम राज्य पुलिस ही है। यह संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। इसके अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों की जांच, कानून व्यवस्था बनाए रखना और पटरियों, पुलों, सुरंगों आदि रेलवे के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

वर्ष 2023 और 2024 में रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़/तोड़फोड़ की सभी घटनाओं में, राज्यों की पुलिस/जीआरपी और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मामले दर्ज किए गए। इसके बाद जांच, अपराधियों की गिरफ्तारी की गई और उन पर मुकदमा चलाया गया।

रेलवे द्वारा राज्य पुलिस/जीआरपी के साथ बेहतर समन्वय, ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए समन्वित कार्रवाई और निगरानी के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

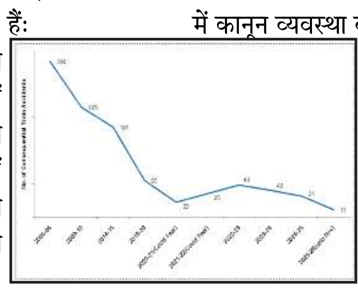

चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों और असुरक्षित इलाकों में रेलकर्मियों, रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ), जीआरपी और सिविल पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से लगातार गश्त की जा रही है।

उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों, असुरक्षित इलाकों में गश्त करने और खतरों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने हेतु विशेष दल गठित किए गए हैं।

रेलवे पटरियों के पास पड़ी सामग्री को हटाने के लिए नियमित अभियान चलाए जा रहे हैं। इसका उपयोग शरारती तत्व रेलवे ट्रैक पर रखकर अवरोध उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं।

रेलवे ट्रैक के पास रहने वाले लोगों को ट्रैक पर अवांछित सामग्री रखने, रेल घटकों को हटाने के बाद होने वाली संभावित घटनाओं के परिणामों के बारे में जागरूक किया जा रहा है और उनसे सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने का अनुरोध किया जा रहा है।

रेलवे राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इनका गठन प्रत्येक राज्य में सम्बंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में किया गया है। इसमें रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ), जीआरपी और खुफिया इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अपराध पर नियंत्रण, मामलों के पंजीकरण, उनकी जांच और रेलवे परिसर के साथ-साथ चलती ट्रेनों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरपीएफ द्वारा राज्य पुलिस/जीआरपी अधिकारियों के साथ सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से घनिष्ठ संपर्क स्थापित किया जाता है। इसमें तोड़फोड़ की घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है और खुफिया जानकारी साझा की जाती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त के अलावा, स्थिति के अनुसार एनआईए और सीबीआई जैसी विशेष एजेंसियां भी शामिल हैं।

केंद्रीय और राज्य खुफिया एजेंसियों के अलावा, आरपीएफ की खुफिया इकाइयां, यानी सीआईबी और एसआईबी को नियमित रूप से जागरूक किया जाता है और उन्हें निर्देश दिए जाते हैं कि वे खुफिया जानकारी एकत्र करें और पुलिस अधिकारियों के समन्वय से तोड़फोड़ के प्रयासों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

ट्रेन संचालन में सुरक्षा सुधारने के लिए भारतीय रेल द्वारा कई उपाय किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के परिणामस्वरूप, दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है। नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाए अनुसार, परिणामी ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या 2014-15 में 135 से घटकर 2024-25 में 31 हो गई है।

गौरतलब है कि 2004-14 की अवधि के दौरान परिणामी रेल दुर्घटनाओं की संख्या 1711 थी (औसतन 171 प्रति वर्ष), जो 2024-25 में घटकर 31 और 2025-26 में (नवंबर 2025 तक) और भी घटकर 11 रह गई।

पिछले पांच वर्षों के दौरान परिणामी रेल दुर्घटनाओं की संख्या नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाई गई है:-

रेल संचालन में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपनाए गए विभिन्न सुरक्षा उपाय इस प्रकार हैं:-

भारतीय रेल में सुरक्षा सम्बंधी गतिविधियों पर व्यय में पिछले कुछ वर्षों में निम्नलिखित रूप से वृद्धि हुई है:-

मानव विफलता के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 31.10.2025 तक 6,656 स्टेशनों पर बिंदुओं और संकेतों के केंद्रीकृत संचालन के साथ विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाए गए हैं

लेवल क्रॉसिंग (एलसी) गेटों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 31.10.2025 तक 10,098 लेवल क्रॉसिंग गेटों पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है।

विद्युत माध्यम से ट्रैक की उपलब्धता की पुष्टि करके सुरक्षा बढ़ाने के लिए 31.10.2025 तक 6,661 स्टेशनों पर पूर्ण ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था की गई है।

कवच एक अत्यंत तकनीकी रूप से उन्नत प्रणाली है। इसके लिए उच्चतम स्तर के सुरक्षा प्रमाणन की आवश्यकता होती है। कवच को जुलाई 2020 में राष्ट्रीय एटीपी प्रणाली के रूप में अपनाया गया था। कवच को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। प्रारंभ में, कवच संस्करण 3.2 को दक्षिण मध्य रेलवे के 1465 आरकेएम और उत्तर मध्य रेलवे के 80 आरकेएम पर तैनात किया गया था।

प्रधानमंत्री की प्रेरणा से शुरू हुई वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की सफलता के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का समावेशी और संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के आयोजन का अभिनव दृष्टिकोण

- कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र की रीजनल कॉन्फ्रेंस 10 से 12 जनवरी, 2026 के दौरान राजकोट में आयोजित होगी
- वीजीआरसी के प्रमोशन के लिए दिल्ली में संवाद-वातार्लाप कार्यक्रम आयोजित
- रशिया, कनाडा और सिंगापुर सहित 20 से अधिक देशों के मिशन और दूतावास के प्रतिनिधि सहभागी हुए
- फिशरीज, पोर्ट, धोलेरा एसआईआर और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर अर्थपूर्ण संवाद का प्लेटफॉर्म

गांधीनगर, 12 दिसंबर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में 2003 से शुरू हुई वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से गुजरात वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर अग्रणी बना है। इतना ही नहीं, गुजरात ने दुनिया भर के उद्योगों-निवेशकों के लिए 'गेट-वे टू द फ्यूचर' की विशेष पहचान स्थापित की है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मिली इस सफलता के बाद राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की मुख्य विशेषताओं, क्षमताओं और आर्थिक विकास की संभावनाओं को उजागर करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) के आयोजन का अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।

संतुलित क्षेत्रीय विकास और समावेशी विकास के लिए मार्गदर्शक

इस वीजीआरसी के राज्य में चार संस्करण आयोजित करने की योजना के अंतर्गत आगामी 10 से 12 जनवरी, 2026 के दौरान राजकोट में सौराष्ट्रझ्र कच्छ क्षेत्र की वीजीआरसी का आयोजन किया जाएगा।

राज्य सरकार ने इस संदर्भ में शुक्रवार, 12 दिसंबर को नई दिल्ली में एक चर्चा-संवाद सत्र का आयोजन किया। इस चर्चा-संवाद सत्र में, वीजीआरसी में देश और दुनिया के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उनके समक्ष वीजीआरसी की विशेषताओं की प्रस्तुति के साथ ही विकास संभावनाओं वाले सेक्टरों को लेकर विचार-विमर्श किया गया।

इस संवाद सत्र में 'क्षेत्रीय आकांक्षाएं, वैश्विक महत्वाकांक्षाएं' थीम के अनुरूप और समावेशी, नवोन्मेषी एवं सतत-टिकाऊ अर्थव्यवस्था के लिए गुजरात की विशेषताएं प्रस्तुत की गईं।

विशेषकर, फिशरीज, पोर्ट्स, धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (एसआईआर) और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर सार्थक संवाद और बीटूबी (बिजनेस-टू-बिजनेस) की संभावनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा-परामर्श हुआ। साथ ही, वीजीआरसी में साझेदार देश बनने के फायदे, नेटवर्किंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे विषयों पर भी वातार्लाप किया गया।

उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप ने चर्चा सत्र में मेहसाणा में आयोजित उत्तर गुजरात क्षेत्र की पहली वीजीआरसी को मिली सफलता और 3.24 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौता ज्ञापनों (एमओयू) की जानकारी दी।

इस संवाद में रशिया, इजरायल, सिंगापुर, यूएई, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, कनाडा, श्रीलंका, ओमान, आइसलैंड, गुयाना, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, कतर, तंजानिया, युगांडा और उज्बेकिस्तान सहित 20 से अधिक देशों के विदेशी मिशन और दूतावासों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के संयुक्त सचिव, केंद्रीय मत्स्य पालन संयुक्त सचिव और इन्वेस्ट इंडिया की राज्य सुविधा टीम तथा गुजरात सरकार के उद्योग एवं खान विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती ममता वर्मा, आर्थिक मामलों की सचिव श्रीमती आरती कंवर, सचिव श्री संदीप कुमार, उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप, पर्यटन सचिव डॉ. राजेन्द्र कुमार, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के सीईओ श्री राजकुमार बेनीवाल, रेजिडेंट कमिश्नर सह मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. विक्रांत पांडे और धोलेरा एसआईआर के सीईओ श्री कुलदीप आर्य मौजूद रहे।

कुशल कार्यबल में वृद्धि और लघु उद्यमों की उत्पादकता में सुधार से भारत में रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि संभव: एनसीएईआर रिपोर्ट

श्रम-केंद्रित विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को दृढ़ करने से जीडीपी की 8 प्रतिशत वृद्धि को बनाए रखने में मदद मिलेगी

ऋण सुविधा में 1 प्रतिशत की वृद्धि भी नियोजित श्रमिकों की अपेक्षित संख्या में 45 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर सकती है

(जीएनएस)। नेशनल कॉंसिल ऑफ एप्लायड इकॉनोमिक रिसर्च (एनसीएईआर) के उपाध्यक्ष मनीष सभरवाल ने 11 दिसंबर, 2025 को "भारत में रोजगार की संभावनाएं: रोजगार के रास्ते" शीर्षक से एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की। एनसीएईआर की प्रोफेसर फरजाना अफरीदी और उनकी शोधकताओं की टीम द्वारा लिखित यह रिपोर्ट देश में रोजगार सृजन के प्रमुख कारकों के रूप में कौशल विकास और लघु उद्यमों की भूमिका पर बल देती है। एनसीएईआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यबल की गुणवत्ता और मात्रा तथा श्रम उत्पादकता बढ़ाने में आने वाली बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि रोजगार में वृद्धि मुख्य रूप से स्वरोजगार में बढ़ोतरी के कारण हुई है, जबकि कुशल श्रम बल की ओर बदलाव की प्रक्रिया धीमी रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि श्रम प्रधान विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को सुदृढ़ करने से जीडीपी की वृद्धि दर को लगभग 8 प्रतिशत पर बनाए रखने में मदद मिल सकती है, जो विकसित भारत के विजन के अनुरूप है।

एनसीएईआर के उपाध्यक्ष मनीष सभरवाल ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, "भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, और यद्यपि इसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी वर्तमान में 128वें स्थान पर है, यह रिपोर्ट रोजगार और समावेशी विकास को प्राथमिकता देने के बहुमूल्य अवसरों को रेखांकित करती है।"

प्रोफेसर अफरीदी ने कहा, 'भारत में स्वरोजगार की प्रधानता उद्यमशीलता की गतिशीलता के बजाय आर्थिक आवश्यकता के कारण है। छोटे किसानों की तरह, अधिकांश लघु उद्यम निर्वाह स्तर पर ही काम करते हैं। भारत को इस वास्तविकता का सामना करना होगा कि उसका रोजगार भविष्य उसके सबसे छोटे उद्यमों की उत्पादकता से जुड़ा है।' मुख्य चुनौती यह है कि गैर-पंजीकृत घरेलू उद्यम पूंजी, उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के निम्न स्तरों के साथ प्रचालन करते हैं।

उन्होंने कहा, 'डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले उद्यम, तकनीक का उपयोग न करने वाले उद्यमों की तुलना में 78 प्रतिशत अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं। यहां तक कि ऋण सुविधा में 1 प्रतिशत की वृद्धि से भी नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों की अपेक्षित संख्या में 45 प्रतिशत की वृद्धि होती है।'

विशिष्ट जनसांख्यिकीय लाभ के बावजूद रोजगार सृजन में बनी हुई चुनौतियों के संबंध में, रिपोर्ट में कहा गया है आपूर्ति पक्ष पर, भारत के कार्यबल को कौशल विकास-विशेष रूप से नई प्रौद्योगिकियों और एआई के आगमन से अत्यधिक लाभ हो सकता है। रोजगार वृद्धि में-खासकर सेवा क्षेत्र में-मध्यम-कुशल रोजगारों का दबदबा है जबकि विनिर्माण क्षेत्र निम्न कौशल-आधारित बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है, "औपचारिक कौशल विकास में निवेश के माध्यम से कुशल कार्यबल की हिस्सेदारी में 12 प्रतिशत अंकों की वृद्धि से 2030 तक श्रम-प्रधान क्षेत्रों में रोजगार में 13 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो सकती है।"

अध्ययन में किए गए सिमुलेशन से पता चलता है कि मध्यम वृद्धि परिदृश्य के तहत औपचारिक रूप से कुशल कार्यबल को बढ़ाने से श्रम-प्रधान क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रोजगार सृजन हो सकता है। इसमें कहा गया है, "कुशल कार्यबल की हिस्सेदारी में 9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि से 2030 तक 93 लाख रोजगार सृजित हो सकते हैं।"

रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए, एनसीएईआर के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. जीसी मन्ना ने कहा कि यह रिपोर्ट रोजगार वृद्धि को गति देने की प्रबल क्षमता वाले प्रमुख सेक्टरों को रेखांकित करती है।

औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान के विजिटिंग प्रोफेसर आदित्य भट्टाचार्य ने कहा, "यह रिपोर्ट भारत को अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में रखती है और उन क्षेत्रों को उजागर करती है जहां देश के पास सुधार और वैश्विक मानकों के साथ मजबूत तालमेल बिठाने के अनूठे अवसर हैं।"

रिपोर्ट में अंतर-क्षेत्रीय संबंधों के गुणक प्रभावों का आकलन करते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि विनिर्माण और सेवाओं के भीतर अपेक्षाकृत अधिक श्रम-प्रधान उप-क्षेत्रों के सकल उत्पादन (जीओ) में मध्यम वृद्धि से 2030 तक कई गुना रोजगार सृजन होगा। विनिर्माण में वस्त्र, परिधान और संबंधित उद्योगों में 53 प्रतिशत और व्यापार, होटल और संबंधित सेवाओं में 79 प्रतिशत अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है।

यह रिपोर्ट विशिष्ट सेक्टरों में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए लक्षित उपायों की अनुशंसा करती है। विनिर्माण क्षेत्र में, उत्पादन-संबंधी प्रोत्साहनों को वस्त्र, परिधान, जूते और खाद्य प्रसंस्करण जैसे श्रम-प्रधान उद्योगों की ओर पुनर्निर्देशित करने से रोजगार सृजन में वृद्धि हो सकती है। सेवा क्षेत्र में, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए नीतिगत सहायता से व्यापक स्तर पर समावेशी रोजगार सृजित किया जा सकता है।

केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन को संबोधित करेंगे

(जीएनएस)। संचार और उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया 13 दिसंबर, 2025 को शाम 4 बजे से महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में आयोजित होने वाले ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।

इस सम्मेलन का उद्देश्य ग्रामीण डाक सेवकों के समर्पण और सेवा को सम्मानित करना है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया पोस्ट की रीढ़ हैं। सम्मेलन का उद्देश्य लोगों को जोड़ने तथा ग्रामीण भारत में डाक, बैंकिंग और बीमा सेवाओं का विस्तार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना भी है।

डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी महानिदेशक डाक सेवा श्री जितेंद्र गुप्ता, डाक सेवा बोर्ड के कार्मिक सदस्य श्री सुवेंदु कुमार स्वैन, महाराष्ट्र और गोवा सर्कल के मुख्य डाक महानिरीक्षक श्री अमिताभ सिंह, डाक सेवा पुणे क्षेत्र के निदेशक श्री अभिजीत बंसोडे और डाक सेवा गोवा क्षेत्र के निदेशक श्री रमेश पाटिल भी उपस्थित रहेंगे।

इस कार्यक्रम में गोवा और पुणे क्षेत्रों के विभिन्न मंडलों से 5500 से 6000 ग्रामीण डाक सेवकों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय मंत्री ग्रामीण डाक सेवा समुदाय के साथ बातचीत करेंगे, आधुनिक और नागरिक-केंद्रित डाक नेटवर्क के लिए अपने दृष्टिकोण के बारे में बताएंगे और उन्हें ग्रामीण समुदायों को सरकारी और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में उनकी भूमिका को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करेंगे।

सम्मेलन के अंतर्गत, श्री सिंधिया डाक और पार्सल वितरण, नए डाक बचत खाते खोलने, डाक जीवन बीमा (पीएलआई) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) पॉलिसी खरीदने, ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को सीधे भुगतान जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन करने वाले ग्रामीण डाक सेवकों को सम्मानित करेंगे।

यह सम्मेलन ग्रामीण भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण के प्रवेश द्वार के रूप में इंडिया पोस्ट को सशक्त बनाने, प्रत्येक डाकघर को नागरिक-केंद्रित सेवाओं के केंद्र में बदलने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन के दौरान प्रतिनिधियों ने बेहद भावुक क्षणों का अनुभव किया

प्रतिनिधिमंडल प्रार्थना करने के लिए हनुमानगढ़ी और सरयू नदी के तट पर गए

(जीएनएस)। काशी तमिल संगमम 4.0 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से आए प्रतिनिधिमंडलों के चौथे बैच ने गुरुवार को एक बेहद भावुक और यादगार दिन बिताया। समूह ने हनुमानगढ़ी स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर और पवित्र सरयू नदी के तट के दर्शन किए। इन अनुभवों ने प्रतिनिधिमंडल पर अमिट छाप छोड़ी।

भगवान श्री राम की प्रतिमा के दर्शन करते हुए प्रतिनिधिमंडल अत्यंत भावुक हो गया। उन्होंने इस क्षण को आध्यात्मिक रूप से सार्थक बताया।

हनुमानगढ़ी में प्रतिनिधिमंडल ने भक्तिमय वातावरण में भगवान श्री हनुमान के मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस यात्रा ने उन्हें आंतरिक शक्ति का अनुभव कराया। उन्होंने बताया कि हनुमानजी की उपस्थिति ने उनमें नए सिरे से आत्मविश्वास जगाया।

दोपहर में प्रतिनिधिमंडल ने सरयू नदी के किनारे समय बिताया। उन्होंने पाया कि काशी तमिल संगम ने आस्था, इतिहास और आध्यात्मिकता के साथ सार्थक जुड़ाव प्रदान किया है, जिसमें श्री राम मंदिर के दर्शन विशेष रूप से यादगार रहे।

काशी तमिल संगमम 4.0 उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक संबंधों को निरंतर मजबूत कर रहा है। किसानों की यह यात्रा इस बढ़ते संबंध का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है।

काशी तमिल संगमम 4.0 के 10वें दिन तमिलनाडु से काशी पहुँचा छठा दल

बनारस रेलवे स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत, छठे दल में महिलाएँ शामिल

(जीएनएस)। तमिलनाडु से काशी तमिल संगमम 4.0 में शामिल होने के लिए छठा दल काशी पहुँच गया है। इस दल में महिलाएँ शामिल हैं। जब यह दल विशेष ट्रेन से बनारस रेलवे स्टेशन पर उतरा, तो उनका पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया।

स्टेशन पर पारंपरिक स्वागत देखकर तमिल दल के सदस्यों में खासा उत्साह देखने को मिला। कई लोगों ने कहा कि काशी में मिल रहा आध्यात्मिक वातावरण उनके लिए अविस्मरणीय है। डमरू वादन की ध्वनि से पूरा परिसर शिवमय हो गया और काशी व तमिलनाडु की सांस्कृतिक एकता की झलक साफ दिखाई दी।

कार्यक्रम के तय शेड्यूल के अनुसार, तमिलनाडु से आए ये डेलिगेट्स आज श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शनझ्रपूजन करेंगे। इसके बाद वे गंगा तट, घाटों तथा शहर के प्रमुख सांस्कृतिक और शैक्षिक स्थलों का भ्रमण भी करेंगे। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि अतिथियों को काशी की समृद्ध विरासत, कला, संस्कृति और अध्यात्म से परिचित कराने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।

दल में शामिल लक्ष्मी काशी पहुँचने पर भावुक हो गईं। उन्होंने कहा, 'हमारा शुरू से सपना था कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें। आज काशी पहुँचकर बहुत खुशी हो रही है।'

लक्ष्मी ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से काशी में आगमन होगा। वह अन्य महिलाओं के साथ दक्षिण भारतीय भाषा में भजन गाती हुई दिखाई दीं। उन्होंने कहा, 'हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि हमारे राज्य के लोगों को उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन का अवसर मिल रहा है। काशी और दक्षिण भारत का रिश्ता काफी पुराना है।'

पेशेवरों और कारीगरों के समूह की हनुमान घाट पर प्रार्थना

प्रतिनिधिमंडल ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती के निवास का दौरा किया और उनकी विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त की

प(जीएनएस)। तमिलनाडु के पेशेवरों और कारीगरों से युक्त प्रतिनिधिमंडल का पांचवां बैच आज काशी तमिल संगमम 4.0 के अंतर्गत हनुमान घाट पहुंचा। उन्होंने प्रार्थना की और समृद्धि और खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। प्रतिनिधिमंडल ने मां गंगा में स्नान करने के बाद घाट पर स्थित प्राचीन मंदिरों में दर्शन करने के साथ-साथ उनके ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की।

प्रतिनिधिमंडल ने हनुमान घाट स्थित महाकवि सुब्रमण्यम भारती के निवास स्थान का दौरा भी किया। उन्होंने निवास से जुड़े व्यक्तियों से बातचीत की और उनके जीवन और योगदान के बारे में जानने में रुचि व्यक्त की। प्रतिनिधिमंडल ने पास के पुस्तकालय जाकर वहां के इतिहास और महत्व के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की।

महाकवि सुब्रमण्यम भारती को तमिल साहित्य और राष्ट्र आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। तमिल के "राष्ट्र कवि" के रूप में पूजनीय महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने काशी में अपने प्रवास के दौरान संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन किया था।

महाकवि भारती के निवास स्थान का दर्शन करने के बाद, प्रतिनिधिमंडल ने कांची मठ पहुंचकर उन्होंने वहां की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रतिनिधिमंडल ने काशी के मध्य स्थित दक्षिण भारतीय मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रसन्नता व्यक्त की।

प्रतिनिधिमंडल का मार्गदर्शन करने वाले वी चंद्रशेखर द्रविड़ घनपति ने बताया कि केदार घाट और हनुमान घाट के आसपास के इलाकों में पीढ़ियों से दक्षिण भारतीय परिवार बसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि कई परिवार पांच या दस पीढ़ियों से काशी में रह रहे हैं, स्थानीय परंपराओं को अपनाते हुए अपनी परंपराओं को भी संरक्षित कर रहे हैं। इससे भगवान शिव की नगरी में उत्तर और दक्षिण भारतीय संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है।

पेशेवरों और कारीगरों के इस प्रतिनिधिमंडल का काशी में निर्धारित कार्यक्रमों में भाग लेने का कार्यक्रम है और बाद में नमो घाट का दौरा भी इसमें शामिल है।

बलरामपुर ब्लॉक में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ, बीडीओ ने दीप प्रज्वलित कर की शुरूआत

(जीएनएस)।

बलरामपुर ब्लॉक में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ, इऊड ने दीप प्रज्वलित कर की शुरूआत

बलरामपुर। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत विकासखंड बलरामपुर में आयोजित 2 दिवसीय अनावासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ आज ब्लॉक सभागार में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन खंड विकास अधिकारी (इऊड) मनोज कुमार ने मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन के साथ किया।

प्रशिक्षण सत्र में मास्टर ट्रेनर मनोज कुमार, देवेंद्र पांडेय, विजय यादव, मीरा देवी, विधि चतुवेर्दी निधि चूवेर्दी कंप्यूटर ऑपरेटर तथा सहायक विकास अधिकारी अशोक दुबे उपस्थित रहे। सभी प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को पंचायत प्रशासन, ड.र.इ. विषय, पारदर्शिता और कार्यप्रणाली से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान कीं।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत सचिव एवं पंचायत सहायक उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से

अश्वनी सिंह, सुनील कुमार यादव, दिनेश मिश्रा, अंकित कुमार, राकेश कुमार, राकेश चौधरी, विकास कुमार, संजीव श्रीवास्तव, हरिशंकर तिवारी, कामता प्रसाद,

महेंद्र कुमार यादव

आदि सचिव प्रशिक्षण में शामिल हुए।

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायतों में सुशासन, पारदर्शिता और कार्यक्षमता को और अधिक सुदृढ़ करना है। और डरइ की जानकारी मिलीबलरामपुर। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत विकासखंड बलरामपुर में आयोजित 2 दिवसीय अनावासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ आज ब्लॉक सभागार में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन खंड विकास अधिकारी (इऊड) मनोज कुमार ने मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन के साथ किया।

प्रशिक्षण सत्र में मास्टर ट्रेनर मनोज कुमार, देवेंद्र पांडेय, विजय यादव, मीरा देवी, विधि चतुवेर्दी निधि चूवेर्दी कंप्यूटर ऑपरेटर तथा सहायक विकास अधिकारी अशोक दुबे उपस्थित रहे। सभी प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को पंचायत प्रशासन, ड.र.इ. विषय, पारदर्शिता और कार्यप्रणाली से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान कीं।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत सचिव एवं पंचायत सहायक उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से

अश्वनी सिंह, सुनील कुमार यादव, दिनेश मिश्रा, अंकित कुमार, राकेश कुमार, राकेश चौधरी, विकास कुमार, संजीव श्रीवास्तव, हरिशंकर तिवारी, कामता प्रसाद, महेंद्र कुमार यादव

आदि सचिव प्रशिक्षण में शामिल हुए।

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायतों में सुशासन, पारदर्शिता और कार्यक्षमता को और अधिक सुदृढ़ करना है। और डरइ की जानकारी मिली

जनपद बलरामपर के थाना म0तराई मिशन शक्ति टीम द्वारा जनपद हरदोई से गुमशुदा लड़की को सकुशल बरामद किया गया

(जीएनएस)। **बलरामपुर**

थाना महराजगंज तराई मिशन शक्ति टीम को ग्राम बरदहवा थाना महराजगंज तराई में दौराने जागरुकता अभियान ग्राम वासियों द्वारा एक अज्ञात लड़की के गांव में रहने की सूचना दिया गया। इस सूचना पर टीम द्वारा लड़की से पूछने पर उसके द्वारा अपना पता चांद बेहटा थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई बताया गया तथा ये भी बताया गया कि मै शमशेर पुत्र शमशाद निवासी बरदहवा थाना महराजगंज तराई के साथ आयी हूं। उक्त दोनो को मिशन शक्ति टीम द्वारा थाना उपस्थित लेकर आया गया ।

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही एवं रोकथाम जुर्म जरायम के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी ललिया देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार तिवारी थाना म0तराई के कुशल नेतृत्व में-

थाना म0 तराई मिशन शक्ति टीम म0उ0नि0 आकांक्षा तिवारी, हे0का0 तेरस राम यादव, का0 प्रमोद कुमार, का0 पवनेश कुमार, म0का0 पूजा यादव, म0का0 अनीता गुप्ता, म0का0 श्वेता मद्धेशिया की टीम द्वारा दुर्गा पुत्री नत्थुलाल व शमशेर पुत्र शमशाद दोनों को थाना स्थानीय पर लाया गया तथा इस सम्बन्ध में जनपद हरदोई से जरिये दूरभाष संपर्क करने पर पता चला कि अपहृता उपरोक्त की गुमशुदगी के सम्बन्ध में थाना बिलग्राम जनपद हरदोई में मु0अ0सं0 609/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत है तथा बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। उक्त के क्रम में थाना प्रभारी बिलग्राम व विवेचक को अवगत कराया गया। विवेचक उ0नि0 अजय कुमार तोमर मय हमराह महिला आरक्षी ममता विश्वकर्मा थाना बिलग्राम जनपद हरदोई के उपस्थित थाना आकर पीड़िता/अपहृता नाबालिक निवासी चांद बेहटा थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई उम्र करीब 15 वर्ष को सकुशल महिला आरक्षी उपरोक्त के सुरक्षार्थ सुपुर्द कर अभि0 शमशेर पुत्र शमशाद निवासी बरदहवा थाना महराजगंज तराई जनपद बलरामपुर को हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण झ

शमशेर पुत्र शमशाद निवासी ग्राम बरदहवा थाना महराजगंज तराई जनपद बलरामपुर उम्र करीब 20 वर्ष

डीएम ने किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जोकहिया का निरीक्षण

आशा बहुओं के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डीएम ने की बैठक, ग्रामस्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर जोर

(जीएनएस)। **बलरामपुर**

जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने आज विकास खंड बलरामपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जोकहिया का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं एवं चिकित्सा व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वार्ड एवं ओपीडी का भ्रमण कर साफ-सफाई, रोगियों की संख्या, चिकित्सकीय सुविधा तथा उपचार प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की।

डीएम ने औषधि वितरण कक्ष में जाकर दवा स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन किया और निर्देशित किया कि समस्त आवश्यक दवाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें तथा मरीजों को दवाओं के वितरण में किसी प्रकार की कोई कमी न आए। उन्होंने टीकाकरण कक्ष और कोल्ड चेन रूम का भी निरीक्षण कर टीकों की सुरक्षित भंडारण व्यवस्था, तापमान नियंत्रण और रिकॉर्ड मेनटेनेंस की

स्थिति की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित मरीजों से सीधे बातचीत की ।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में अस्पताल आने वाले मरीजों को असुविधा नहीं होनी चाहिए तथा सभी को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त हों।

आशा बहुओं के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर की बैठक, ग्रामस्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर जोर

निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में कार्यरत आशा बहुओं के साथ बैठक की और ग्रामस्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आशा स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे प्रमुख स्तंभ एवं महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जो गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, टीकाकरण, परिवार नियोजन सहित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को गांव-गांव तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

डीएम ने आशा बहुओं के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि उनके बिना ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रभावी रूप से संचालित नहीं हो सकतीं। उन्होंने आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाए जाने के निर्देश दिए तथा उनके कार्यों को और प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान किए जाने की बात कही।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आशा बहु गांवों में नियमित भ्रमण करें, टीकाकरण और मातृ-शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी करें और किसी भी समस्या की सूचना समय से स्वास्थ्य विभाग को दें।

इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मुकेश रस्तोगी, संबंधित एमओआईसी व अन्य संबंधित अधिकारी / कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

प्राणायाम और मेडिटेशन को दिनचर्या का बनाएं हिस्सा

शहीद रविंद्र कुमार रावमावि पाल्हावास में प्राणायाम और मेडिटेशन का कराया अभ्यास

(जीएनएस)।

रेवाड़ी। शहीद रविंद्र कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव पाल्हावास में शुक्रवार को श्री रवि शंकर महाराज की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्यों ने ध्यान एवं योग क्रिया` का अभ्यास करवाया। उन्होंने विद्यार्थियों को प्राणायाम और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

पाल्हावास राजकीय विद्यालय

की प्राचार्य शोभा रानी भारद्वाज ने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्य सुमन यादव, सुषमा यादव और डॉ. सुमन ने विद्यार्थियों को वार्म अप, प्राणायाम और इसके बाद मेडिटेशन की क्रियाओं का अभ्यास करवाया। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि तन के साथ-साथ मन का भी स्थिर और एकाग्रचित्त होना बहुत आवश्यक` है। हमें दैनिक जीवन में प्राणायाम और मेडिटेशन की क्रियाओं का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय के स्टाफ सदस्य और काफी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

समाधान शिविर में प्राप्त हुई शिकायतों की डीसी ने की समीक्षा

अधिकारियों को लंबित शिकायतों का शीघ्र निपटारा किए जाने के निर्देश दिए

रेवाड़ी जिला में लंबित शिकायतों का तेजी से किया जा रहा है निवारण

(जीएनएस)।

रेवाड़ी। चंडीगढ़ से जिलावार समाधान शिविर में आई शिकायतों की रिपोर्ट ले रहे एसीएस राजशेखर वुंद्रू ने इस बात पर संतोष जाहिर किया कि रेवाड़ी जिला में लंबित शिकायतों का तेजी से निपटान किया जा रहा है। उन्होंने इस कार्रवाई के लिए डीसी अभिषेक मीणा की सराहना की।

समीक्षा बैठक में यह सामने आया कि शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग, राजस्व विभाग और नगर परिषद की कुछ शिकायतें अभी लंबित हैं। डीसी अभिषेक मीणा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपसी तालमेल रखते हुए इन शिकायतों में से एक भी दस दिन से अधिक समय तक पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने जिस उद्देश्य से समाधान शिविर का आयोजन शुरू किया है, वह मकसद हर हाल में पूरा होना चाहिए। आम जन की जो वाजिब शिकायत है, उसका समय पर निवारण किया जाए।

उन्होंने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के लिए इन पर नियमित निगरानी रखें और त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। बैठक में एडीसी राहुल मोदी, सीटीएम जितेन्द्र कुमार, डीडीपीओ एसपी बंसल, बीडीपीओ अनिल कुमार, क्रीड के प्रोगामर नीरज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

पृथ्वी राज चौहान की प्रतिमा का केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने किया अनावरण

युवाओं को देश के महान योद्धाओं के पराक्रम, साहस और धैर्य के बारे में दें जानकारी

महान योद्धाओं की प्रतिमा स्थापित करना सराहनीय कार्य

(जीएनएस)।

रेवाड़ी। केंद्रीय सांख्यिकी, कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन एवं योजना राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शुक्रवार को बावल के गांव धरचाना में स्थापित की गई महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का भव्य स्वागत एवं अभिवादन किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से बावल के विधायक डा. कृष्ण कुमार, कोसली के विधायक अनिल यादव, संजय छौक्कर, महेंद्र सिंह, दशरथ सिंह चौहान, शीला सिंह शेखावत, प्रताप सिंह मौजूद रहे।

केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गांव धरचाना में स्थापित की गई पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा युवाओं को अद्भुत साहस, पराक्रम और धैर्य की प्रेरणा देगी। हमें युवा पीढ़ी को देश के महान योद्धाओं, क्रांतिकारियों और महापुरुषों के इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी देनी चाहिए। युवाओं को महान योद्धाओं के पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पृथ्वी राज चौहान ग्रामीणों को पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा स्थापित करने पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने आह्वान किया कि हमें अन्य गांवों में भी शूरवीर योद्धाओं की प्रतिमा स्थापित नहीं आते। हमें उनके जीवन और बलिदान से सीख लेनी चाहिए कि मातृभूमि से बढकर हमारे लिए और कुछ नहीं है। कोसली के विधायक अनिल यादव ने भी ग्रामवासियों को

ऐसे महान योद्धा हुए हैं, जिन्होंने 17 बार अपने दुश्मन को हरा दिया था। वहीं आंखों से अंधा` हो जाने के बाद भी अपने शब्दभेदी बाण से दुश्मन मुहम्मद गौरी को मार गिराया था। हमें पृथ्वी राज चौहान के जीवन प्रेरणा लेते हुए देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने धरचाना गांव के कर उनका सम्मान करना चाहिए। इस अवसर पर ग्रामीणों द्वारा विभिन्न मांग पत्र भी केंद्रीय मंत्री को सौंपे गए, जिन पर उचित कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया।

इस अवसर पर विधायक डा. कृष्ण कुमार ने` पृथ्वीराज चौहान को नमन करते हुए कहा कि ऐसे महापुरुष बार-बार इस धरती पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की विशाल प्रतिमा की स्थापना पर बधाई दी।`

इस अवसर पर जिला परिषद के चेयरमैन मनोज यादव, वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि अनिल रायपुर, ब्लॉक समिति बावल के चेयरमैन छत्रपाल सिंह, एसडीएम मनोज कुमार, बीडीपीओ शुभम सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

केन्द्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने करीब 100 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

अधिकारियों को भी विकास४ योजनाओं में देना चाहिए सक्रिय योगदान- राव इंद्रजीत सिंह

(जीएनएस)।

रेवाड़ी। केंद्रीय सांख्यिकी, कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन एवं योजना राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शुक्रवार को नगर परिषद, रेवाड़ी में शहरी विकास से जुड़ी करीब 100 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करते हुए इन्हें आम जनता के लिए समर्पित किया। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि इन परियोजनाओं के नामकरण में अमर स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम तथा पूर्व मुख्यमंत्री स्व. राव बिरेन्द्र सिंह को भी तवज्जो दी गई है।

` केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है। आने वाले

चार सालों में उनका और पार्टी के स्थानीय विधायकों का यह प्रयास रहेगा कि आम जनता के हित और रेवाड़ी जिला को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए अधिक से अधिक विकास परियोजनाएं लागू करवाई जाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भी इन विकास परियोजनाओं का प्रारूप तैयार करने और इन्हें धरातल पर लाने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। जनप्रतिनिधि के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों का भी यह दायित्व बनता है कि विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के बाद रेवाड़ी हरियाणा का सबसे आगे बढ़ता हुआ जिला है, इसके चहुंमुखी विकास के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 89 लाख रुपए की लागत से नारनौल रोड पर नगर परिषद बाउंड्री में बनने वाले मेन एंट्रेंस गेट, 126.25 लाख रुपए की लागत से वार्ड नंबर 31 में राम तलाई जोहड़ पर बनने वाले पाथ-वे और बाउंड्री वॉल, 89 लाख रुपए की लागत से गढ़ी बोलनी रोड पर नगर परिषद बाउंड्री में बनने वाले मेन एंट्रेंस गेट, 139.38 लाख रुपए की लागत से वार्ड नंबर 28 में ठठेरा कॉलोनी में आईपीबी टाईल रोड, 89 लाख रुपए की लागत से दिल्ली रोड पर नगर परिषद बाउंड्री में बनने वाले मेन एंट्रेंस गेट, 89 लाख रुपए की लागत से बावल रोड पर नगर परिषद बाउंड्री में बनने वाले मेन एंट्रेंस गेट व 165 लाख रुपए की लागत से वार्ड नंबर 12 में शिव नगर पार्ट ए कॉलोनी में आईपीबी टाईल रोड विकास कार्यों का शिलान्यास किया। वहीं राव तुलाराम पार्क में 84.44 लाख रुपए की लागत से हॉल, लाइब्रेरी, गेट, फुटपाथ व शौचालय के पुनर्निर्माण, वार्ड नंबर 30 गुलाबी बाग में महावाला जोहड़ पर 78.90 लाख रुपए की लागत से पाथ-वे और बाउंड्री वॉल, अनाज मंडी रोड़ पर 242.86 लाख रुपए की लागत से रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज टैंक सहित संत कबीर चौक नियर नया गांव दौलतपुर, राव बिरेन्द्र सिंह मार्ग व राव तुलाराम मार्ग का उद्घाटन किया।

` इस अवसर पर रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव रेवाड़ी में तेजी से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। रेवाड़ी को स्वच्छता के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने आमजन से भी स्वच्छता अभियान में भागीदार बनते हुए रेवाड़ी को और सुंदर बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बावल के विधायक डा. कृष्ण कुमार, कोसली के विधायक अनिल यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली, नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में एसडीएम सुरेश कुमार, भाजपा नेता मा. हुकमचंद, महामंत्री हिमांशु पालीवाल, उपाध्यक्ष प्रवीन शर्मा, वनीता पीपल` सहित अनेक नगर पार्षद व अधिकारी मौजूद रहे।

बाइक चोरी करने के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

(जीएनएस)।

रेवाड़ी। थाना धारूहेड़ा पुलिस ने बाइक चोरी करने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान राजस्थान के जिला खैरथल तिजारा के गांव मिलकपुरी निवासी आसबदीन उर्फ कल्लु के रूप में हुई है। पुलिस इस मामले में तीन आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

जांचकर्ता ने बताया कि गांव तीतरपुर निवासी विक्रम सिंह ने अपनी शिकायत में बताया था की गत 3 मार्च वह अपनी बाइक पर करुनेश वाटिका धारूहेड़ा में एक शादी के प्रोग्राम में गया था। उसने अपनी बाइक को वाटिका के बहार खड़ी किया था। जिसे कोई नाम पता

नामालूम व्यक्ति चोरी करके ले गए है। जिस पर पुलिस ने थाना धारूहेड़ा में चोरी का मामला दर्ज करके मामले में संलिप्त तीन आरोपी रासीद`, सफीक खान उर्फ टुल्ला व मोहम्मद इरफान को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जो इस मामले में पुलिस ने वीरवार को मामले में संलिप्त एक और आरोपी राजस्थान के जिला खैरथल तिजारा के गांव मिलकपुरी निवासी आसबदीन उर्फ कल्लु को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को पेश अदालत करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।